स्वरूप हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। यदि उन्हें कोई सहायता नहीं दी गई, तो वह दिन दूर नहीं, जब यह उद्योग समाप्त हो जाएगा।

IMA

अतः अनुरोध है कि कैलेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा बनाई जा रही पी०वी०सी० फिल्मों पर लगाया गया 31½ प्रतिशत उत्पादन-शुल्क समाप्त कर दिया जाए और कैलेंडरिंग कारखानों द्वारा खरीदे गए मौलिक कच्चे माल पर वसूल किया गया शुल्क वापस किया जाए।

(ii) Need to effect basic changes in the field of research

श्री मूल चन्द डागा (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, वैज्ञानिक जगत में भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करना है। विज्ञान के चरण बहुत तेज और तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिए भारत सरकार ने करीब 150 प्रयोगशालाएं खोल रखी हैं, जहां बड़े और छोटे वैज्ञानिकों द्वारा शोधकार्य होता है। केन्द्रीय सरकार हर साल 570 करोड़ रुपया इन शोध प्रयोगशालाओं पर खर्च करती है। यह बात निर्विवाद सही है कि इन शोधशालाओं से आज लगभग शून्य है, जबकि खर्च उसकी तुलना में बढ़ा-चढ़ा है। क्या आज तक कभी इस बात का मूल्यांकन किया गया है कि ये शोधशालाएं समाज की कौन-कौन सी जरूरतों को मद्देनजर रख कर काम कर रही हैं और इनकी उपलब्धियां पिछले पांच वर्षों में जो हुई हैं, क्या वे सन्तोषजनक हैं? आज वैज्ञानिक जगत में बढ़े हुए देश अमरीका, रूस, यूरोप में वैज्ञानिकों और उद्योगों के बीच में गहरा जिन्दा लेन देन दिखाई पड़ता है। समस्या और समाधान के बीच जो सुन्दर और सलोने पुल बंधे हुए हैं, भारत में उन का सर्वथा अभाव है। इन शोधशालाओं में वैज्ञानिकों की ज्यादा ताकत शोध करने में नहीं, फार्म भरने में और प्रोग्रेस रिपोर्ट को तैयार करने में लगाई जाती है। आज कई वैज्ञानिक शोधशालाओं में शानदार उपलब्धि के बजाय शानदार प्रोग्रेस रिपोर्ट उपलब्ध हो सकती है। इस प्रकार के माहौल ने अच्छे वैज्ञानिकों को विदेश जाने के लिए मजबूर किया है और जो बाहर हैं, वे भारत लौटने को आतुर नहीं हैं। अतः सरकार को शोध के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन और परिवर्धन करना होगा ताकि जो धनराशि खर्च होती है, उससे समाज और देश को लाभ मिल सके और वैज्ञानिक जगत में भारत प्रगतिशील देशों की दौड़ में पीछे न रहे।

(iii) Need for setting up proposed Railway Coach Factory in Palghat, Kerala

***SHRI V.S. VIJAYARAGHAVAN** (Palghat): Sir, Kerala is an industrially backward State. For the past many years a demand has been raised for setting up a railway coach factory in that State. The Government of Kerala had promised to provide all infrastructural facilities at concessional rates. As a matter of fact, there is no major railway installation in Kerala.

Now, there is a report that an expert team has been sent to Kerala to make preliminary study for setting up a coach factory in Kerala. It is indeed a very heartening step. I hope that the Government will take an expeditious decision on the report of this team. In this context I may mention that Palghat is the most suitable place for setting up this factory. All the required facilities are available there. Therefore, I earnestly request the Government to take speedy steps to set up this coach factory at Palghat itself.

(iv) Need to take steps to increase the rice production in the country

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak): In spite of the commendable achievements made in our agriculture, especially on the rice front, breaking the stagnation level of 53 to 54 million tonnes and reporting a score of 57 million tonnes in the year 1983-84, India's achievement in per hectare yield in rice is actually poorer than many countries, including some developing ones.

The experience with high-yielding varieties has shown that when the ecology of the rice

*Original speech was delivered in Malayalam.

[Shri Arjun Sethi]

field is changed by the application of more water and fertiliser, the threat to yield caused by the triple alliance of weeds, pests and pathogens could become serious. Countering the risk effectively will be particularly important for the small farmers who cannot otherwise be expected to show an interest in making requisite investments in inputs which are vital to the success of high-yielding varieties programme.

Most important perhaps is the correction of yield disparities between regions. In rice yields, Punjab leads with 2,961 kilograms per hectares followed by Haryana. The average per hectare yield is 952 kilograms in Assam, West Bengal, Orissa, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, which account for 66.8 per cent of the land under paddy against the national average of 1308 kilograms.

It is imperative on the part of the Government to rectify the distortions that exist in agriculture and take steps to increase production of rice.

(v) Policy in regard to prices of agricultural products

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : सभापति महोदय, दैनिक उपयोग की वस्तुएं हों अथवा अन्य प्रकार की, मूल्य वृद्धि का सिलसिला हर चीज में इस देश में इस प्रकार प्रारम्भ हुआ जिसे किसी प्रकार भी रोक पाना सम्भव नहीं हो सका। साढ़े तीन दशकों में देखा जाए तो हर वस्तु का मूल्य कृषि क्षेत्र के उत्पादन में दस गुना से लेकर 20 गुना तक तथा औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में 20 गुना से लेकर 100 गुना तक बढ़ा है। हमारे देश में हर तीसरे महीने औद्योगिक उत्पादन के मूल्य आम तौर पर बढ़ते हैं, पर किसान द्वारा उत्पादित अनाज और जायद फसलों के दाम हमेशा उस समय गिर जाते हैं जब किसान की फसलें पक कर खेत से घर आना शुरू होती हैं। परन्तु उसके घर से जब अनाज और जायद फसलें बिककर सरकारी भण्डारों अथवा निजि व्यवसायों के गोदामों में भर जाती हैं और उपभोक्ता के रूप में किसान तथा आदमी को पुनः उन्हें खरीदना पड़ता है तो फसल के समय की कीमत से ड्योढ़ी-दूनी रों की चुकाने पर वही चीजें उसे पुनः मिल पाती हैं। मईसाल के तौर पर गत नवम्बर-दिसम्बर, 1983 में जहां थोक भाव में गेहूं प्रति कुन्टल 225 रु०, चना 225 रु० से 400 रु० प्रति कुन्टल, जो 142 रु० से 150 रु० प्रति कुन्टल, सरसों 500 रु० से 600 रु० प्रति कुन्टल, अरहर लगभग 500 रु० प्रति कुन्टल थी। वही अब जब किसान के खेत में पक कर तैयार हुई और घर से बाजार तक पहुंचने की नौबत आई तो गेहूं के दाम गिरकर 150 रु० से 170 रु० प्रति कुन्टल, चना 275 रु० से 300 रुपए प्रति कुन्टल, जौ 100 से 110 रु० प्रति कुन्टल, सरसों 400 रु० प्रति कुन्टल, अरहर 300 रु० प्रति कुन्टल किसान के घर से बिकना प्रारम्भ हो गई है। इसके विपरीत औद्योगिक उत्पादन में किसान की जरूरत की वस्तुएं जैसे ट्रैक्टर, कृषि यन्त्र, बिजली, पानी खाद, सीमेंट ईंट, लोहा, कपड़ा आदि सभी वस्तुओं के दाम नवम्बर-दिसम्बर, सन् 1983 के बाद 5 से 10 फीसदी तक बढ़ गए हैं।

इस देश का असंगठित किसान बराबर लुट रहा है। सरकार पर भी मात्र संगठित वर्गों का दबाव है। इसलिए किसान की आबादी का सरकार पर कोई असर भी नहीं। देश की अर्थ-व्यवस्था का मूल्यांकन जहां औद्योगिक उत्पादन पर होता है, वहीं कृषि प्रधान देश में उसके मूल्यांकन का प्रमुख महत्व कृषि उत्पादन पर है। परन्तु किसान की उपेक्षा उसे हताश किये है। सरकार से मांग है कि किसान के साथ न्याय किया जाए। समय-समय पर फसलों पर किसान के उत्पादित अनाजों और जायद फसलों के किस प्रकार मूल्य घटे-बढ़े हैं, उसी दर से औद्योगिक उत्पादों जैसे कपड़ा, लोहा, ट्रैक्टर, डीजल, ईंट सीमेन्ट आदि किसान और आम आदमी की जरूरत की चीजों के दाम भी घटने-बढ़ने चाहिए। आशा है सरकार देश की 80 परसेन्ट किसानों की लूट को रोकने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी।